रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत

शुभांगी माथुर
नई दिल्ली, 18 मई

भारत का स्पष्ट रुख

- रूसी तेल के लिए अमेरिकी छूट का नवीनीकरण नहीं होने से भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा
- पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में रूसी कच्चे तेल की बड़ी भूमिका रही है

भारत की तेल शोधन कंपनियां रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेंगी, भले ही 16 मई को रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत को दी गई छूट समाप्त हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

देश में तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत से ही अमेरिकी छूट के आधार पर रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में कहा कि रूसी तेल के लिए अमेरिकी छूट का नवीनीकरण नहीं होने से भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिका ने विभिन्न देशों को 17 अप्रैल या उससे पहले जहाजों पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रखने की अनुमति दी थी, जो 16 मई तक मान्य थी। शर्मा ने कहा, 'मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हम छूट से पहले और उसके दौरान रूस से (कच्चे तेल) खरीद रहे थे। हम अभी भी खरीद रहे हैं। ओएमसी के लिए रूसी तेल खरीदने का वाणिज्यिक औचित्य होना चाहिए। कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त कच्चा तेल आवंटित किया गया है। छूट हो या न हो, इससे हमारी आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके लिए सभी प्रयास किए गए हैं।' पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में रूसी कच्चे तेल की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर डाला है।

तेल विपणन कंपनियों ने 16 मई को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की, जो चार वर्षों में पहली वृद्धि थी। इसका मकसद नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। शर्मा ने कहा कि हालिया मूल्य वृद्धि के बाद राज्य के स्वामित्व वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं को पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलिंडर की बिक्री पर प्रतिदिन लगभग 750 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके पहले रोजाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये नुकसान हो रहा था।

शर्मा ने कहा, 'अभी अंडर रिकवरी है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस मिलाकर अब यह रोजाना 750 करोड़ रुपये के आसपास है।'

अधिकारी ने कहा कि सरकार ने ओएमसी को हो रहे मौजूदा घाटे की भरपाई के लिए आर्थिक सहयोग की कोई योजना नहीं बनाई है।

सरकार ने 15 मई को डीजल पर निर्यात शुल्क को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर लगभग 16.50 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर लगभग 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया था। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क लगभग 3 रुपये प्रति लीटर लगाया गया था।

भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने कहा कि भारत आए एक एलपीजी कैरियर एसवाईएमआई से माल उतारने का काम पूरा कर लिया है, जिसने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार किया था। मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगाए जहाज 19,965 टन एलपीजी लेकर आया है और 16 मई को गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचा।

पूंजीगत वस्तु आयात पर निर्भरता घटाने का आग्रह

कृति अंबे
नई दिल्ली, 18 मई

निर्यात बढ़ाने पर नजर

- विदेशी वस्तुओं के लिए छोटी सी तरजीह भी घरेलू उद्योग को कमजोर कर सकती है
- वित्त वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस भी सहायता की जरूरत है, केंद्र सरकार उसे मुहैया कराने को तैयार है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को उद्योग से विशेषकर पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में आयात पर अपनी निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। सरकार द्वारा पश्चिम एशिया संकट के बीच सोने और चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद मंत्री ने यह कहा है।

गोयल ने हितधारकों से वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार पोर्टल पर आयात रुझानों का अध्ययन करने और घरेलू विनिर्माण और आयात के विकल्पों की पहचान करने का आग्रह किया। उन्होंने देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इससे भारत के व्यवसायों को लिए महत्त्वपूर्ण अवसर मिले हैं।

गोयल ने भारतीय व्यापार महोत्सव वेबसाइट की शुरुआत के मौके पर कहा, 'विदेशी वस्तुओं के लिए छोटी सी तरजीह भी घरेलू उद्योग को कमजोर कर सकती है।' यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया 96.35 के नए निचले स्तर पर बंद हुआ है।

अमेरिका और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में शुरू हुए संघर्ष के बाद रुपया 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले सप्ताह आयात पर लगाम लगाने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। गोयल ने भारतीय उद्योग से राजकोट, जालंधर, लुधियाना, बटाला और पुणे जैसे घरेलू विनिर्माण केंद्रों से पूंजीगत वस्तुओं की सोर्सिंग का पता लगाने के लिए भी कहा। पिछले पांच वर्षों में भारत के कुल आयात में पूंजीगत वस्तुओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस भी सहायता की जरूरत है, केंद्र सरकार उसे मुहैया कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद सरकार ने अगले 5 साल में भारत का निर्यात 2 लाख करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल निर्यात 863.10 अरब डॉलर था, जिसमें 441.80 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात शामिल है।

मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली ने भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार तक तरजीही पहुंच सुरक्षित करने के लिए लगभग 38 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है, जिससे उन्हें कम आयात शुल्क पर बेचा जा सके। उन्होंने कहा, 'ये समझौते धीरे-धीरे प्रभावी होंगे, जिसमें ओमान एफटीए 1 जून से लागू होने की संभावना है। कुछ अन्य पर कागजी कार्रवाई चल रही है और उसके बाद उन्हें लागू कर दिया जाएगा।'

यात्रा खर्च घटाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें बैंक व वित्तीय संस्थान

संजीव मुखर्जी और दीपक पटेल
नई दिल्ली, 18 मई

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मितव्ययिता के उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यात्रा संबंधी खर्चों में कटौती करना और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

सर्कुलर में कहा गया है, 'अगर भौतिक बैठकों की खास जरूरत न हो तो सभी बैठकें, समीक्षा और परामर्श व प्रस्तुतियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं।'

इस सर्कुलर को बिज़नेस स्टैंडर्ड ने देखा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि संगठनों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सहित शीर्ष अधिकारियों की विदेश यात्रा भी तय सीमा से कम रखी जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, विदेश में होने वाली बैठकों में वर्चुअली भाग लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा सरकार ने संगठनों से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने को भी कहा है।

आदेश में कहा गया है, 'सभी संगठनों को अपने प्रधान कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में अपने द्वारा किराए पर लिए गए पेट्रोल और डीजल वाहनों को यथासंभव इलेक्ट्रिक कारों से बदलने का लक्ष्य रखना चाहिए।'

इसके अलावा मंत्रालय ने सरकारी वित्तीय संस्थानों से कहा कि 'वाहनों के मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ईवी में परिवर्तित किया जाए।' सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की मंजूरी के बाद ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

मितव्ययिता अभियान केवल वित्तीय सेवा विभाग तक ही सीमित नहीं है। उर्वरक विभाग ने एक आंतरिक नोट में यह भी कहा कि कर्मचारियों को कार-पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल सुविधाओं का उपयोग करने और जहां तक संभव हो घर से काम को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिकांश बैठकें अब वर्चुअली आयोजित की जानी चाहिए और कर्मचारियों को घरेलू पर्यटन के लिए जाकर विदेशी मुद्रा में योगदान करने की सलाह दी जाती है।

विभाग ने यह भी कहा कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों को रासायनिक उर्वरकों की खपत को 25-50 प्रतिशत तक कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मितव्ययिता अभियान के हिस्से के रूप में 1 जून से 15 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी 'सेव फार्म्स अभियान' शुरू करने की घोषणा की। किसानों के बीच संतुलित और जरूरत के आधार पर उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने पर अभियान का ध्यान होगा, ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो और अत्यधिक इनपुट के उपयोग को कम किया जा सके। *(साथ में एजेंसियां)*

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

AUTOFURNISH
STYLE YOUR RIDE

AUTOFURNISH LIMITED

(Formerly known as Autofurnish Trading Limited and Autofurnish Trading Private Limited)
Corporate Identification Number: U51101DL2015PLC279742

Our Company was originally incorporated on May 05, 2015 as 'Autofurnish Trading Private Limited, as a private limited company under the Companies Act, 2013 bearing Corporate Identification Number U51101DL2015PTC279742 pursuant to Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, Delhi. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on May 23, 2024. A fresh Certificate of Incorporation consequent to conversion was issued on August 27, 2024 by the Registrar of Companies, ROC, CPC, Manesar Haryana and consequently the name of our Company was changed from "Autofurnish Trading Private Limited" to "Autofurnish Trading Limited" bearing Company's Corporate Identification Number U51101DL2015PLC279742. The name of our company was subsequently changed to "Autofurnish Limited" and fresh certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, ROC, CPC, Manesar Haryana dated October 14, 2024. For more details of Incorporation and Registered Office of our Company, please refer to chapter titled 'Our Business' and 'Our History and Certain Other Corporate Matters' on page no. 145 and 195 of this Prospectus.

Registered office: K-55, Udyog Nagar, Peeragarhi, Nangloi, West Delhi, New Delhi-110041
Tel: +91 8375818888 E-mail: corporate@autofurnish.com, Website: www.autofurnish.com | **Contact Person:** Ms. Srishti Narang, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. PUNEET ARORA AND MR. RUPPAL WADHWA

NOTICE TO THE INVESTORS:
CORRIGENDUM TO PROSPECTUS DATED MAY 14, 2026

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 35,61,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF AUTOFURNISH LIMITED ("THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 41/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 31/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 1460.01 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UPTO 1,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 41/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 31/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 73.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,81,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT A PRICE OF RS. 41/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 31/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 1386.21 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE UPTO 26.34% AND 25.02% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 313 OF THIS PROSPECTUS

ATTENTION INVESTORS -CORRIGENDUM

The Company has filed the Prospectus dated May 14, 2026 with the Registrar of Companies, Delhi ("ROC") on May 14, 2026 in respect of the Initial Public Offer ("IPO") of the Company, which is scheduled to open for subscription on May 21, 2026 and close on May 25, 2026.

In reference to the aforesaid Prospectus dated May 14, 2026, certain changes have been made with respect to the Minimum Application Size and Maximum Application Size appearing on page no. 357 of the Prospectus. Accordingly, investors are requested to take note of the following changes:

SECTION VII – ISSUE INFORMATION

ISSUE STRUCTURE

Particulars of the Issue	Net Issue to Public	Market Maker Reservation Portion
Minimum Application Size	**For Individuals Investors who applies for minimum application size:** two lots (Each lot size consists 3000 equity share) Equity Shares at an offer price of Rs. 41 each so that the Application Value exceeds ₹2,00,000.	1,80,000 Equity Shares at Rs 41/-each.
Maximum Application Size	**For Other than Individual Investors:** Such number of Equity Shares in multiples of 3,000 Equity Shares not exceeding the size of the Net Issue, subject to applicable limits.	1,80,000 Equity Shares at Rs. 41 each.

The Pre-Issue Advertisement published on May 16, 2026, should be read in conjunction with this corrigendum.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
NOVUS CAPITAL ADVISORS Empowering Ambitions Elevating Growth **NOVUS CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED** **(Formerly known as Fast Track Finsec Private Limited)** **Address:** Office No. V-116, 1st Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 **Tel:** +91 11 43029809; **Email:** mb@novuscaps.com **Contact Person:** Ms. Sakshi/ Mr. Wajahat Ali Khan **Website:** www.novuscaps.com **SEBI registration number:** INM000012500 **CIN:** U65191DL2010PTC200381	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address: -** D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 **SEBI Registration No.:** INR000003241 **Contact Person:** Mr.Anuj Rana **Email**: ipo@skylinerta.com **Website**: www.skylinerta.com **Tel No**: +91-11-40450193-97, 26812682, 011-26812682 **CIN:** U74899DL1995PTC071324

OFFER PROGRAMME

BID/ISSUE OPENS ON:	BID/ISSUE CLOSES ON:
May 21, 2026	May 25, 2026

For Autofurnish Limited
(Formerly known as Autofurnish Trading Limited)
Sd/-
Srishti Narang
Company Secretary and Compliance officer

Date: - May 18, 2026
Place: - New Delhi

केकी मिस्त्री का बढ़ सकता है कार्यकाल

एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफा देने के बाद तीन माह के लिए इस पद पर नियुक्त केकी मिस्त्री के कार्यकाल को विस्तार मिलने की उम्मीद है। इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक इस पद पर उम्मीदवार को चुनने तक मिस्त्री के पद पर कायम रहने की संभावना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद मिस्त्री को 19 मार्च, 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक का अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 19 जून, 2026 को समाप्त होने वाला है। सूत्र ने बताया, 'पूर्णकाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश जारी है। यदि आवश्यक हुआ तो नए व्यक्ति की पहचान और नियुक्ति होने तक वर्तमान अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष को अधिकतम तीन महीने के लिए पद पर बने रहने के लिए कहा जा सकता है।' एचडीएफसी बैंक को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। *बीएस*

लिबर्टी म्युचुअल ने बढ़ाई हिस्सेदारी

आतिरा वारियर
मुंबई, 18 मई

एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने कारोबार की जमीन बनाने के लिए भारत लिबर्टी म्युचुअल के लिए महत्त्वपूर्ण बाजार है

अमेरिका की लिबर्टी म्युचुअल इंश्योरेंस ने सोमवार को कहा कि उसने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (एलजीआई) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर ली है। इसने सितंबर 2025 में लिबर्टी जनरल में अपनी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 55.40 प्रतिशत कर लिया था, उसके बाद फिर से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है।

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, लिबर्टी म्युचुअल इंश्योरेंस ग्रुप की कंपनी समिट एशिया इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और इनाम सिक्योरिटीज का एक संयुक्त उद्यम है। दिसंबर 2025 तक इसमें इनाम सिक्योरिटीज की 26 प्रतिशत और डीपी जिंदल के स्वामित्व वाले डायमंड डीलट्रेड की 18.6 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। लिबर्टी इंटरनैशनल इंश्योरेंस एपीएसी के प्रेसीडेंट मैथ्यू जैक्सन ने कहा, 'एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने कारोबार की जमीन बनाने के लिए भारत लिबर्टी म्युचुअल के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार है। यहां के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और विकास के महत्त्वपूर्ण अवसर से लाभ मिलेगा। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से हमें व्यवसाय को और बढ़ाने और अपनी वैश्विक क्षमताओं को सीधे बाजार में लाने में मदद मिलेगी।' सरकार ने इस महीने की शुरुआत में बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी थी। निवेश के बेहतर नियम और विदेशी कंपनियों को प्रबंधन अधिकार मिलने से उनकी भारतीय बीमा क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है, जिसमें गैर-जीवन बीमा खंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आईसीआईसीआई बैंक के पास प्रमुख हिस्सेदारी रहेगी

सुब्रत पांडा
मुंबई, 18 मई

आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार को कहा कि वह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी बहुल हिस्सेदारी बरकरार रखने का इरादा रखता है। इससे जीवन बीमा कंपनी के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

बैंक ने एक्सचेंज को बताया, 'हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी बहुल हिस्सेदारी बरकरार रखने का इरादा रखते हैं। इससे हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता तय होती है।' यह बयान प्रूडेंशियल पीएलसी (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई बैंक का संयुक्त उद्यम भागीदार) द्वारा रविवार को हुई घोषणा के बाद आया है। इसमें उसने भारती लाइफ इंश्योरेंस में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के बाद सूचीबद्ध बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम करने की योजना बताई थी। वर्तमान नियमों के अनुसार कोई भी संस्था एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। अभी आईसीआईसीआई बैंक के पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 50.89 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि प्रूडेंशियल पीएलसी के पास लगभग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेंशियल पीएलसी से लगभग 2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। इससे उसकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी और वह बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। वहीं, प्रूडेंशियल अपनी शेष हिस्सेदारी का लगभग 10 प्रतिशत ब्लॉक डील के जरिए मुख्य रूप से म्यूचुअल फंडों को बेचने की संभावना है। प्रूडेंशियल पीएलसी व आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, हिस्सेदारी विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से 12-18 महीने का समय मांग सकते हैं। प्रूडेंशियल पीएलसी ने ईमेल का जवाब नहीं दिया।

शुरुआती कारोबार में सोमवार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयर 10 प्रतिशत तक गिर गए, लेकिन कुछ हद तक संभल गए। अंततः बीएसई पर शेयर 3.64 प्रतिशत गिरकर 515.75 रुपये पर बंद हुआ।

निवेश उतार-चढ़ाव बफर रखने की अनिवार्यता खत्म

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए 'निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व' (आईएफआर) बनाए रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह प्रावधान निवेश के मूल्य में गिरावट के जोखिम से बचाव के लिए अतिरिक्त बफर के रूप में रखा जाता था।

केंद्रीय बैंक ने 'वाणिज्यिक बैंक—निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (द्वितीय संशोधन) निर्देश, 2026' जारी करते हुए कहा कि बाजार जोखिम और निवेश से जुड़े सतर्कता संबंधी ढांचे में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया गया है। भारत में शाखा मॉडल के तहत संचालित विदेशी बैंकों के लिए यह राशि सीधे भारतीय बही-खातों में रखे वैधानिक रिजर्व या ऐसे हस्तांतरणीय अधिशेष में डाली जाएगी, जिसे बैंक के भारत में संचालन के दौरान देश से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए आईएफआर से संबंधित अलग-अलग परिपत्र भी जारी किए हैं। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के मामले में आईएफआर में राशि का हस्तांतरण अनिवार्य विनियोजन के बाद शुद्ध लाभ से किया जाएगा। *भाषा*

एफसीआई 50,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगा

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) 3 महीने की अवधि के लिए अनुसूचित बैंकों से 50,000 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण जुटाने जा रहा है। इसमें अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 'ग्रीन शू' विकल्प भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह धनराशि खाद्यान्न की खरीद एवं वितरण से उत्पन्न नकदी प्रवाह असंतुलन को पाटने के लिए जुटाई जा रही है। इस संबंध में जमा निविदाएं 22 मई को खोली जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि निविदा के तहत कुल उधारी किसी भी समय 75,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। यह अल्पकालिक ऋण बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर लिया जाएगा।

खाद्य ऋण के लिए एफसीआई को उपलब्ध भारत सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की गारंटी इन उधारियों पर लागू नहीं होगी। निविदा की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव 31 अगस्त तक वैध रहने चाहिए और ऋण वितरण एफसीआई की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार चरणों में किया जाएगा। एफसीआई राशन कार्ड धारकों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद एवं वितरण से जुड़ी सरकार की नोडल एजेंसी है। *भाषा*

बीएस सूडोकू 5593

परिणाम संख्या 5592

7	6				3			
	8	5			6		9	
4		2				3		5
				8				
			4			2		
			3		9			
						7		
9	5		1		2			8
		7				1	4	

7	1	6	4	2	3	8	5	9
8	2	9	5	1	7	6	3	4
3	5	4	9	8	6	1	7	2
4	6	5	1	3	9	7	2	8
9	7	3	8	5	2	4	6	1
1	8	2	6	7	4	5	9	3
6	3	1	7	9	8	2	4	5
2	4	8	3	6	5	9	1	7
5	9	7	2	4	1	3	8	6

कैसे खेलें ?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

मुश्किल ★★★★☆

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।